

न्यायालय, अपर समाहर्ता, मधुबनी।  
आदेश-पत्रक  
( देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129 )

आदेश पत्रक तारीख.....तक

जिला.....मधुबनी संख्या.- 79/18-19.

वाद का प्रकार : बिहार भूमि सुधार एवं अधिकतम सीमा निर्धारण अधिनियम की धारा- 16(3) अरिया सिलिंग अपील वाद

अर्जीकार:- जीबछ यादव

प्रतिपक्षी:-ईस्क लाल यादव वगैरह

आदेश का क्रम संख्या और तारीख		आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित।
01-06-19	<p>यह अपील वाद की प्रक्रिया भूमि सुधार उप समाहर्ता, झंझारपुर के न्यायालय वाद संख्या-03/2011-12 में पारित आदेश के विरुद्ध अपील आवेदन पर समाहर्ता महोदय के न्यायालय में अभिलेख संख्या-101/2012-13, 228/18-19 से प्रारम्भ हुई।</p> <p>जिला दण्डाधिकारी, मधुबनी के पत्रांक-3053/जि0वि0दिनांक-06.09.2018 द्वारा इसे सुनवाई कर निष्पादनार्थ इस न्यायालय में हस्तान्तरित किया गया।</p> <p>तदनुपरांत इस न्यायालय में वाद की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई। प्रक्रिया संचालन के क्रम में सरकार के संयुक्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-235(8)/रा0 दिनांक-05.04.2019 से बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिभूमि अर्जन) (संशोधन) अधिनियम 2019( बिहार अधिनियम 6, 2019) के अधिसूचना की गजट की प्रति जो विधि विभाग, बिहार पटना की अधिसूचना सं0 एल0जी0-01-15/2018/1569/लेज दिनांक-25.02.2019 द्वारा अधिसूचना की संसूचित की गई है जिसमें अधिनियम 1961 की धारा-16 की उप धारा (3) को निरसित की गई है। उक्त अधिनियम की धारा-16 में निम्नलिखित नई उप धारा- (4) जोड़ी गई है:-</p> <p>“(4)(i) इस अधिनियम की धारा-16 की उप धारा-(3) के निरसन के पश्चात् राज्य सरकार, राजस्व पर्वद, बिहार भूमि न्यायाधिकरण, प्रमंडलीय आयुक्त, समाहर्ता, अपर समाहर्ता, भूमि सुधार उप समाहर्ता अथवा किसी अन्य न्यायालय में लंबित सभी मामले अथवा कार्यवाही उपर्युक्त समझी जायेगी।</p> <p>(ii) इस अधिनियम की धारा-16 की उप धारा-(3) को निरसन के अनुरूप में पहले वैधरूप से जमा की गई कय राशि उसके 10% के समतुल्य राशि के साथ, जमाकर्ता को बिना सूद के लौटा दी जायेगी।</p> <p>चूंकि विभागीय अधिसूचना के अनुसार धारा-16(3) को उपर्युक्त कर दी गई है इसलिए इस न्यायालय में प्रक्रियाधीन उक्त वाद की कार्यवाही को उपर्युक्त समझा जाय।</p> <p>आदेश की प्रति के साथ विभागीय अधिसूचना के आलोक में अग्रोत्तर कार्रवाई हेतु निम्न न्यायालय का मूल अभिलेख वापस लौटावें।</p>	

लेख्यपित  
अपर समाहर्ता  
01/6/19



अपर समाहर्ता, 01/6/19  
मधुबनी।